

70

यायलय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. / 2016 निगरानी माल.

निग. 2203-I16

1. बाबूलाल पुत्र भगरी एवं चतुरी पत्नि बाबूलाल (फौत वारिसान)

दिनांक 4-7-16 को
प्रो. राज. प्र. नं. 112/16
का प्रो. 511/16

- अ-वृन्दावन पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।
- ब-कमलसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।
- क-कूलसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।
- द-महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।

4-7-16

सभी जाति जाटव निवासीगण-ग्राम करोला,
तहसील व जिला मुरैना
इ-श्रीमती गीताबाई पत्नि श्री केशवसिंह पुत्री
स्व. श्री बाबूलाल निवासी भीमनगर आगरा
उ.प्र. हाल निवासी ग्राम करोला
तहसील व जिला मुरैना म०प्र०

Dr. Bhanu Singh
4/7/17

- 2. मुन्नीलाल जाटव पुत्र हरिविलास जाटव,
निवासी- बलुआपुरा मौजा करोला,
परगना मुरैना म.प्र.
- 3-देवीराम पुत्र श्री सुखा।
- 4-होतम सिंह पुत्र श्री सुखा
- 5-मालवी पुत्री सूखा पत्नी फुन्दी,
निवासीगण शिवलाल का पुरा, मौजा मोडरी,
तहसील मुरैना।
- 6-म.कलिया पुत्री सूखा पत्नी सुधरसिंह ज.प्र.,
निवासी उत्तमपुरा, मुरैना म०प्र०

विरुद

- (1) राजवीर पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाटव निवासी मोती ग्रीज जलालपुर, लशकर,
ग्वालियर म.प्र. -अनावेदक
 - (2) तहसीलदार मौजा करौला
 - (3) रा० नि०. मौजा करौला
 - (4) पटवारी मौजा करौला
- अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म.प्र. प्र० क्र० 55/14-15 दितिय अपील
में पारित आदेश दिनांक 30.6.16 के विरुद म.प्र. १० राजस्व की धारा 50 के
अंतर्गत निगरानी अन्दर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तु है।

110

देवीराम

महेन्द्रसिंह

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

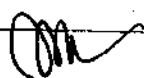
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2203-एक/2016 निगरानी

जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षधारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-16	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसीलदार मौजा करौला तहसील मुरैना के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-6-16 में अंकित अनुसार भूमि का कब्जा वापिस दिलाने जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 1/2611-12 अ-70 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30-9-14 पारित करके आवेदकगण को भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 11/2004-05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 13-4-15 से अपील स्वीकार की गई एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-9-14 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 55/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2016 से अपील स्वीकार की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13-4-15 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।</p> <p>3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों</p>	

K
1/8



प्रकरण क्रमांक 2203-एक/2016 निगरानी

के तर्क सुने गये तथा आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का विवाद व्यवहार न्यायालय में चला है तथा माननीय उच्च न्यायालय तक मामला पहुंचा है किन्तु विचाराधीन प्रकरण स्वत्व के विवाद का अथवा माननीय न्यायालयों के आदेशों के पालन में स्वत्व के लेख के शासकीय अभिलेख में अंकन का नहीं है अपितु तहसील न्यायालय का मूल मामला संहिता की धारा 250 के अंतर्गत रिकार्डेड भूमिस्वामी को कब्जा दिलाये जाने वावत् है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 में प्रावधान किया गया है कि कृषक की भूमि पर किसी अन्य द्वारा कब्जा करने के दो वर्ष के भीतर पीढ़ित कृषक संहिता की धारा 250 के अधीन वाद ला सकता है परन्तु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार के समक्ष जो मूल वाद लाया गया है उसमें ऐसा कहीं भी अंकन नहीं है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक क्रमांक-1 की भूमि पर किस दिनांक को अथवा किस वर्ष के बेजा कब्जा किया गया है, अपितु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत धारा 250 के मूल दावे में अनावेदक क्र-1 ने स्वयं बताया है कि आवेदकगण ने स्याई निषेधाज्ञा का वाद वर्ष 2002 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मुरैना के समक्ष क्रमांक 50 ए/2002 प्रस्तुत किया था अर्थात् वर्ष 2002 के पूर्व से वादविचारित भूमि पर आवेदकगण कब्जा किये हुये थे और माननीय व्यवहार न्यायालय से तत्सम्बन्ध में स्याई निषेधाज्ञा चाह रहे थे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कब्जे की अवधि के सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष इन कारणों से सही निर्णय होना आभाषित है जिसके विपरीत अर्थ निकालते हुये अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 30-6-2016 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-4-15 को निरस्त करने में भूल की है

R
MK

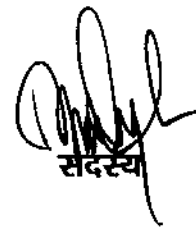
AM

जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-4-15 के अंत में दिये गये निष्कर्ष के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि तहसील न्यायालय में दो बार प्रकरण अनावेदक क-1 के अनुपस्थित रहने से अदम पैरबी में निरस्त हुआ है एवं दूसरी बार प्रकरण पुनर्स्थापित करते समय आवेदकगण को सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2011-12 अ-70 में की गई इस प्रकार की कार्यवाही दूषित प्रक्रिया पर आधारित रही है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में भूल नहीं की है अपितु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने संहिता की धारा 250 में विहित प्रावधानों पर ध्यान न देते हुये आदेश दिनांक 30-6-2016 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-4-15 को निरस्त करने में त्रुटि की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।

R
1/11


सदस्य